विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

गरीबी से मुक्ति हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति व पर्यावरण से बेहतर कोई उपाय नहीं

यजुर्विद संहिता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है: दारिद्र्यपाशाद्रुरुतो न दुःखम्, शिक्षारोग्येणविमुक्तिरिष्टा। शान्तिप्रकृत्यासहिता च सिद्धिः, नास्त्यत्रमार्गोऽपरतोहिश्रेष्ठः।। तात्पर्य यह है कि गरीबी के बंधन से बड़ा कोई दुःख नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य से ही वांछित मुक्ति प्राप्त होती है। शांति और प्रकृति के साथ सिद्धि प्राप्त होती है। इससे बेहतर कोई और मार्ग नहीं है। इसी बात को यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है: दारिद्र्यादधिकः निःसन्देहंनास्ति, तस्यविमुक्तयेशिक्षारोग्यशान्तिपर्यावरणानि श्रेष्ठानि साधनानि, अन्येषांन्यूनत्वात्। तात्पर्य यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, और उससे मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और पर्यावरण से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं देखा जाता। आज की चर्चा पुनः इसी विषय पर है।

मेरा जीवन एक साधारण गाँव में शुरू हुआ जहाँ अकूत गरीबी थी। मेरे पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और मैं प्रायः उनको इस संघर्ष में देखता था कि कैसे वे एक ओर अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और दूसरी ओर सरकारी अफसरों और नेताओं से हाथ जोड़कर अपने पदस्थापन स्थान के विकास के लिए याचना करते थे। मैंने तब इस बात को स्वयं जिया कि कैसे गरीबी न केवल जीवन की गुणवत्ता को कम करती है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा को भी छलनी कर देती है। इस अभिशाप से मुक्ति पाने की छटपटाहट में मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और पर्यावरण के महत्व को आत्मसात और क्रियान्वित किया।

शिक्षा ने मेरे लिए विश्व के बंद दरवाजे खोले। शिक्षा मेरे लिए ज्ञान की वह रोशनी लेकर आई, जिसने मुझे अपनी स्थितियों को समझने और उन्हें बदलने की रणनीति और शक्ति दी। स्वास्थ्य ने मुझे यह सिखाया कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और निर्मल मन निवास करता है, और यही निर्मल मन व्यक्ति के समग्र कल्याण का बीज है। शांति ने मुझे आंतरिक संतुलन और सामंजस्य के चमत्कारी प्रभाव को समझाया, जो हमारे भीतर सहयोग और सद्भावना को बढ़ाता है। हमारे आसपास का पर्यावरण और उसको बेहतर रखने के प्रति सचेत रहने से मुझे यह समझ पाना सुलभ हुआ कि प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन केमूल आधार हैं, और इनकी सुरक्षा करना हमारी असल में हमारी अपनी भलाई के लिए अनिवार्य है।

इस प्रकार, मेरी कहानी आपको यह सिखा सकती है कि गरीबी से लड़ने और विजय पाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, और पर्यावरण कोसाथ लेकर चलना होगा। ये चारों स्तंभ व्यक्तिगत जीवन के साथ ही समग्र समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम इन स्तंभों को सशक्त बनाते हैं, तो हम न केवल गरीबी के विरुद्ध एक प्रबल लड़ाई लड़ सकते हैं, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रख सकते हैं जो अधिक समृद्ध, स्वस्थ, और शांतिपूर्ण हो।

अपनी जीवन यात्रा में मैंने यह भी सीखा कि जब समाज एक साथ मिलकर काम करता है, तो बदलाव लाना तुलनात्मक रूप से शीघ्रतापूर्वक संभव हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, शांति की दिशा में काम करना, और पर्यावरण की रक्षा करना–ये सभी कार्य तब और अधिक प्रभावी होते हैं जब हम सभी इसमें साझा प्रयत्न करते हैं। मेरी कहानी यह भी दर्शाती है कि गरीबी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे पराजित करने के लिए हमारे पास शक्तिशाली रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, और पर्यावरण के माध्यम से हम व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही पूरे समाज और राष्ट्र को भी उन्नित की ओर ले जा सकते हैं। इस दिशा में मिलजुल कर किया गया कार्य एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहाँ गरीबी मात्र इतिहास का हिस्सा बन कर रह जाए।

शिक्षा और कौशल का महत्व तो जगजाहिर है। इससे न केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त होते हैं, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होता है, उसे प्रायः शोषण का सामना करना पड़ता है। जब वही व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, तो वह न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने जीवन की बेहतरीहेतु सही निर्णय ले सकता है।

शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य भी गरीबी से मुक्ति का एक अनिवार्य साधन है। बीमारियों से मुक्त एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य में अधिक सक्षम होता है और तुलनात्मक रूप से अधिक आय अर्जित कर सकता है। इसके उलट, एक बीमार व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दुष्प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ होना और उनकी गुणवत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध और सुखी समाज की नींव रख सकता है।

यह आवश्यक है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और शांति के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें और इन्हें अपनी राष्ट्रीय नीतियों का केंद्र बिंदु बनाएं। इस प्रकार, हम एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे जहाँ हर नागरिक के पास अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का अवसर होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही शांति भी गरीबी से मुक्ति का एक अनिवार्य घटक है। एक शांतिपूर्ण समाज में, व्यक्तियों, परिवारों और समाज को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के बेहतर अवसर प्राप्त होता है। जिस समाज में हिंसा और अशांति होती है उसमें सतत विकास की संभावनाएं घट जाती हैं और गरीबी बढ़ती जाती है। फलतः, शांति को बढ़ावा देना और आपसी संघर्षों को कम करना गरीबी से मुक्ति के लिए अनिवार्य है।

गरीबी को मिटाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और शांति के साथ–साथ पर्यावरण का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरणीय स्थिरता से हमारे संसाधन सुरक्षित रहते हैं, जो कि सतत आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय विकास और लोगों के कल्याण में मौलिक भूमिका निभाते हैं। जब पर्यावरण संरक्षित होता है, तो यह खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करता है, और स्वच्छ जल, वायु और मृदा प्रदान करता है। इस प्रकार, पर्यावरणीय स्थिरता प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्रों के साथ ही मानव समाज के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है। इसलिए, गरीबी उन्मूलन की हमारी रणनीतियों में पर्यावरणीय संरक्षण को भी प्रमुख स्थान देना चाहिए। प्राकृतिक जलवायु समाधान जिसमें कार्बन पृथक्करण और संचय, जैव–विविधता का संरक्षण, और आजीविका में सुधार शामिल हैं, एक ऐसा रास्ता देते हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण भी करते हैं।

इन चारों स्तंभों – शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और पर्यावरण – को सुदृढ़ करने से ही गरीबी के चक्र को तोड़ा जा सकता है और एक समृद्ध समाज की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकारें और समाज के सभी वर्ग इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से निवेश करें। इन मूलभूत कारकों को सम्हाले बिना गरीबी के विरुद्ध एक प्रभावी और निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।

यदि एक देश अपने बच्चों और नागरिकों को उच्चकोटि की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरणीय सुरक्षा, और शांतिपूर्ण जीवन नहीं दे सकता, तो वास्तव में उसके पास देने के लिए और क्या बचता है? ये सभी तत्व न केवल एक समृद्ध समाज की नींव हैं, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण हैं। एक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें और अपने नागरिकों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, और शिक्षित भविष्य प्रदान करें। यदि हमारा देश अपने नागरिकों को उच्चकोटि की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरणीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करने में सफल होता है, तो यह व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को तो बढ़ाएगा ही साथ ही समाज के समठा विकास को भी सुनिश्चित करेगा। इन मूलभूत कारकों को ध्यान रखकर तय की गई प्राथमिकता ही वह आधार है जिस पर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है।

इस विश्लेषण में हम आने वाले समय में यह स्पष्ट करेंगे कि कैसे शिक्षा नागरिकों को नई तकनीकें और विचार सीखने में मदद कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे उन्हें अधिक उत्पादक बना सकती हैं, पर्यावरणीय संरक्षण कैसे संसाधनों की रक्षा कर सकता है, और शांति कैसे हमारे समाज को अधिक सहयोगी और सद्भावपूर्ण बना सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण के माध्यम से प्राप्तनिष्कर्ष समाज और सरकारों को इन क्षेत्रों में नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे गरीबी कम होने के साथ ही देश की समग्र प्रगति भी सुनिश्चित होगी।

हम इस श्रृंखलाबद्ध विश्लेषण को इस आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह ज्ञान, गरीबी को मिटाने के लिए समाज और सरकारों को एक नई दिशा देगा। जब एक देश अपने बच्चों और नागरिकों को उच्चकोटि की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरणीय सुरक्षा, और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करने में सफल होता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि समाज के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करता है। ये सभी तत्व एक समृद्ध समाज की नींव हैं और हर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल हमारे देश की समग्र उन्नति सुनिश्चित होगी, बल्कि यह हमारे नागरिकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने में भी मदद करेगा। यह आवश्यक है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और शांति के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें और इन्हें अपनी राष्ट्रीय नीतियों का केंद्र बिंदु बनाएं। इस प्रकार, हम एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे जहाँ हर नागरिक के पास अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का अवसर होगा।

हम इस बात को समझते हैं कि गरीबी एक जटिल समस्या है जिसका समाधान एक क्षेत्र में कार्य करने से नहीं, अपितु एक समन्वित और समग्र दृष्टिकोण से ही हो सकता है। इसलिए हमारी श्रृंखला विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों और अनुभवों को साझा करेगी, और शोध–आधारित विचारों को आगे लायेगी, जिससे नवाचार और सुधार के लिए प्रेरणा मिल सके। अंत में, हम आशा करते हैं कि यह श्रृंखला न केवल जागरूकता बढ़ाएगी बल्कि समाज और सरकारों को उन नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी जो वास्तव में गरीबी को कम करने और हमारे देश को एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में सहायक होंगे।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय,
(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

खोया पाया की समीक्षा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राम जल सेतु तक

रामपाल जाट

'भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड' में पंजाब तथा हरियाणा के एक–एक सदस्य हैं किंतु राजस्थान का कोई सदस्य नहीं है। जबकि राजस्थान इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। हरिके बैराज पर नियंत्रण नहीं होने से राजस्थान की भागीदारी के पानी में भी अनेक बार कटौती की जाती है। 'इंदिरा गांधी नहर परियोजना' में 8.6 एमएएफ पानी में से राजस्थान को 7.59 एमएएफ पानी ही प्राप्त हो रहा है। राजस्थान की भागीदारी का 0.6 एमएएफ पानी नहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त जब भी पानी की आवक में कमी होती है तो हरिके बैराज पर पंजाब का नियंत्रण होने से राजस्थान की भागीदारी का पानी कम कर दिया जाता है। राजस्थान निचले भाग (डाउनस्ट्रीम) में होने से सदैव ही पानी प्राप्त करने में घाटे में रहता है। इसी प्रकार नोहर सिद्धमुख नहर से 0.47 एमएएफ पानी प्राप्त होना था किंतु उसमें से 0.30 एमएएफ पानी ही प्राप्त हो रहा है एवं 0.17 एमएएफ हरियाणा ने रोक रखा है। परिणामतः राजस्थान के नोहर, भादरा एवं सिद्धमुख क्षेत्र को पानी की आपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है।

राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य यमुना जल हथिनी कुंड पर 577 तथा ओखला हेड पर 386 मिलियन घन मीटर पानी राजस्थान की भागीदारी में आया था किंतु 30 वर्ष उपरांत भी अभी तक यह पानी भी राजस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है। गुड़गांव नहर की क्षमता में बढ़ोतरी का समझौते का ज्ञापन–अनुबंध (एमओयूए) होने पर भी हरियाणा ने अभी तक अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है। इसी प्रकार राजस्थान और हरियाणा तथा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के मध्य 17 फरवरी 2024 को यमुना जल के वितरण के लिए हथिनी कुंड पर 577 मिलियन घन मीटर पानी ताजेवाला हेड से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा चुरु, झुन्झनू एवं अन्य जिलों को सिंचाई –पेयजल का पानी जुलाई से अक्टूबर की अवधि में देने का एमओयू होने के उपरांत भी हरियाणा ने यमुना बेसिन में तीन स्थान रेणुकाजी, लखवार एवं किशु पर पानी के संग्रहण की व्यवस्था कर ली है।

बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध में गुजरात की 40 प्रतिशत तथा राजस्थान की भागीदारी 16प्रतिशतआरम्भिक रूप से थी। वर्ष 1966 के समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ जाने के उपरांत राजस्थान की भागीदारी 40 प्रतिशत तथा गुजरात की भागीदारी 16 प्रतिशत रह जाती है। इस समझौते के अनुसार वर्ष 2006 में नर्मदा का पानी खेड़ा जिले को प्राप्त हो गया किंतु 19 वर्षों में भी राजस्थान की भागीदारी का 40 प्रतिशत पानी अभी तक राजस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है।

'दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है' इन्ही कटु अनुभवों के आधार पर चंबल सहित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर 3 जून 1999 को दोनों राज्यों के मध्य लिखित समझौता हुआ। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इसका अनुमोदन 25 अगस्त 2005 को किया गया था। तब राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे। यह सुखद आश्चर्य है कि समझौता करने वाले दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे तथा अनुमोदन करने वाले दोनों मुख्यमंत्री भाजपा के थे। इनमें से किसी ने भी छोटा मन नहीं रखा वरन् दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के कार्य में उत्साहपूर्वक सकारात्मकता का प्रदर्शन किया। इस समझौते के बाद ही मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी पर मोहनपुरा एवं कुंडालिया बांधों का निर्माण कराया गया। इन कार्यों के लिए मध्य प्रदेश ने विश्व बैंक से ऋण लिया था। उसकी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए राजस्थान के जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव ने अनापत्ति दी थी। उक्त समझोते के अनुसार मध्य प्रदेश को अनापत्ति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य पहले ही आरंभ कर दिया था।

दोनों राज्यों की जनता के हित में यह विलक्षण समझौता धरातल पर आया था। जिसमें प्रत्येक राज्य को अपनी भूमि पर बांध या उस जैसा कोई भी निर्माण अपनी भूमि पर करने, अपने राज्य के कैचमेंट एरिया के पानी का उपयोग के आधार पर परियोजना तैयार करने तथा दूसरे राज्य के कैचमेंट एरिया के 10ङ्क से अधिक पानी का उपयोग नहीं करने पर अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई थी। राजस्थान में इसी समझौते के आधार पर स्वयं के नियंत्रण एवं संचालन को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय जल आयोग की देखरेख में वर्ष 2017 में 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया था।

देश के प्रधानमंत्री की धारणा के अनुसार पानी का महत्व राजस्थान से अधिक कोई नहीं जानता. इसलिए जलशक्ति मंत्रालय की कमान राजस्थान को सौंपी गयी थी। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक की अवधि में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के कारण इस समझौते को शून्य करने की कार्यवाही राजस्थान की जनता को सदैव चुभती रहेगी। राजस्थान की जनता इस प्रकार की जनहित की बलि देने जैसी कार्यवाही करने वालों को कभी क्षमा नहीं करेगी। राजस्थान का नियंत्रण एवं संचालन में बाधा उत्पन्न करने तथा राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा को कम करना राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है।

पार्वती–कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना पर तैयार नये प्रारूप में इस परियोजना में कुन्नू बेसिन के पानी को राजस्थान से काटकर मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। इसके बदले में पार्वती नदी से पानी लिया जाना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश एव राजस्थान के लिए कुन्नू और पार्वती से पानी प्राप्ति हेतु 75 प्रतिशत निर्भरता का प्रावधान किया गया है। इससे 50 प्रतिशत निर्भरता की अपेक्षा प्राप्त पानी की मात्रा आधी रहेगी। क्योंकि 50 प्रतिशत निर्भरता के अनुसार 4 वर्ष में से 2 वर्ष पानी का संठाहण किया जा सकता है। जबकि 75 प्रतिशत निर्भरता के अनुसार 4 वर्ष में से 1 वर्ष ही पानी का संग्रहण किया जाएगा। कुन्नू नदी का पूर्ण पानी मध्यप्रदेश को प्राप्त होगा जबकि पार्वती नदी में दोनों प्रदेशों की भागीदारी होने एवं मध्य प्रदेश के ऊपरी बेसिन (अप स्ट्रीम) होने के कारण राजस्थांन को प्राप्त होने वाले पानी की कटौती की सम्भावना बनी रहेगी। वैसे भी पार्वती नदी पर मध्य प्रदेश सात से अधिक परियोजनाएँ तैयार कर चुका है। इनमें सोनचिरी, रामवासा, बकोरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, सेकरी एवं सुल्तानपुर आदि है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच किया गया समझौता ज्ञापन–अनुबंध (एमओए) समानता पर आधारित नहीं होने के कारण न्याय संगत नहीं है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी पर 2013–14 से 2018–19 तक मोहनपुरा एवं कुंडालिया बांध बना लिए थे। अब पार्वती नदी पर पातनपुर बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। इन बांधों के द्वारा 1100 मिलियन घन मीटर पानी तो मध्य प्रदेश ने पहले ही सुरक्षित कर लिया। इसे सम्मिलित करने पर मध्य प्रदेश को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 4,742 मिलियन घन मीटर है। जबकि राजस्थान में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा 3405 मिलियन घन मीटर है अर्थात 1337 मिलियन घन मीटर पानी मध्य प्रदेश को अधिक आवंटित किया गया है। इस परियोजना के पानी की गणना में पुनर्चक्रित 522 मिलियन घन मीटर पानी को जोड़ना कल्पनावलम्बित होने से रोचक तथ्य है। कल्पना के आधार पर देश में ही नही बल्कि विश्व में भी एसी प्रणाली अब तक धरातल पर नही उतरी है।

मध्य प्रदेश में कुंडालिया तथा मोहनपुरा बांधों का कार्य वर्ष 2018–19 तक 5 वर्षों में पूरा कर लिया गया था। जबकि मूल 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वर्ष 2017 में तैयार होने के बाद 8 वर्ष में कार्यपूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाया है। बल्कि पेयजल योजनायों के पूर्ण होने का कार्यकाल भी राज्य में वर्ष 2054 तक निश्चित किया गया है। राजस्थान में सिंचाई परियोजना का कार्य मध्यप्रदेश की तुलना में पिछडने का तथ्य स्पष्ट है।

वर्ष 2019 से 2024 तक केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री ने इस परियोजना को अटकाना, लटकाना एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को भटकाना आरंभ रखा, तब धुआं उठा था। अब केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों के कारण इस परियोजना के मूल स्वरूप में आग दिखाई देने लगी है। जिन्होंने पक्षपात नहीं करने की सौगंध खाई थी वे ही पानी की मात्रा घटाने के उपरांत उपयोग बढ़ाने के द्वारा इस परियोजना के लाभान्वितों को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। उपलब्धता घटना तथा उपयोग बढ़ना परियोजना को असफलता की और धकेलने वाला कदम है। जिस व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी हो, उसे खुजली चलने लगे तो सुखचैन समाप्त हो जाता है। सरकार चलाने वाले चुनाव जीतने जैसे निजी स्वार्थ के लिए राज्य के सार्वजनिक हितों के स्थान पर स्वयं के हित की साधना में लग जाए तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरा–तेरा का भाव छोटे मनों के कारण होता है। वे अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को आहत करते हैं। उनके पास न्याय का अवसर आने पर वे अन्याय करते हैं। यही स्थिति राजस्थान में खेत को पानी के उद्घोष को धरातल पर उतारने में हो रही है। ऐसे जन प्रतिनिधि–मंत्रीगण संविधान की सौगंध को मिटाने पर तुले रहते हैं। इसी का परिणाम है कि 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' के गणितीय वैज्ञानिक आधार पर तैयार मूल स्वरूप को बिगाड़ने पर उतारू हैं। स्वार्थ के अंधेपन के कारण एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई है। जिस परियोजना को 3921 मिलियन घन मीटर पानी की उपलब्धता में से 3509.14 मिलियन घन मीटर के उपयोग के आधार पर तैयार किया गया था। उपयोग होने वाले पानी की मात्रा घटाकर 3405 मिलियन घन मीटर कर दी गयी। तदोपरांत भी परियोजना को विस्तारित कर दिया गया, जिससे पानी की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होगी।

इस दिशा में सम्मिलित 26 बांधों के अतिरिक्त पूर्व के बने हुए 15 अन्य बांधों को जोड़ दिया गया। जिसमें पेयजल के मंत्री ने चांदसेन को जुड़वा दिया। इनको देखकर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने 200 मिलियन हेक्टर पानी के संग्रहण के लिए कृत्रिम बांध के नाम पर पुष्कर में तथा इसी होड़ में केन्द्रीय मंत्री ने 300 मिलियन घन मीटर के अलवर के सरिस्का की पहाड़ियों में कृत्रिम बांध की प्रस्तावना सम्मिलित करा दी। आश्चर्य तो यह है कि चाहत के अनुसार पुराने बांध अस्तित्व में नहीं होने पर भी नये बांध प्रस्तावित कर दिये गये। ऐसी स्थिति में राज्य के मुखिया भी क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी परियोजना में सम्मिलित बंध बरेठा से आगे पानी ले जाने के लिए 'सुजान गंगा–भरतपुर लिंक' को जुड़वा दिया। इनके लिए बजट 2024–25 में घोषणा कर दी गई और उसी की अनुपालना में 18 फरवरी 2025 को टेंडर भी कर दिए गए। इसके अतिरिक्त विकास के नाम पर परियोजना के मार्ग में आने वाले 158 छोटे तालाबों की सूक्ष्म सिंचाई विकास परियोजना प्रस्तावित कर दी गई है। पानी की पर्याप्त सुनिश्चित उपलब्धता के परीक्षण के उपरांत इस प्रकार की योजनाए स्वागत योग्य होती है किन्तु पानी की उपलब्धता को घटाने के बाद भी जनप्रतिनिधियों द्वारा परियोजना के मूलस्वरूप को बिगाड़ाना उचित नही कहा जा सकता।

यह राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की सदिच्छा है कि उसके 'खेत को पानी' मिले। इसमें कोई असहमत नहीं हो सकता। इसके लिए अधिकाधिक सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता है। उनके लिए पानी की आवश्यकता 'सिंधु जल समझौते' को निरस्त कर भी पूर्ण की जा सकती है। पूर्व में हुए समझौतों की पालना से इसे संभव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विस्तृत भूभाग के वर्षा जल का संग्रहण कर भी 'खेत को पानी' उपलब्ध कराया जा सकता है। इस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए ही जन प्रतिनिधियों, मंत्रियों एवं सरकारों की प्रासंगिकता है। केन्द्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के मुखिया एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण से तो पानी प्राप्त करने के उपरांत परियोजनाएं बनाने की आशा एवं आकांक्षा जन सामान्य को रहती है। ये सभी इस कठिन कार्य से बचते हुए तैयार भोजन को ग्रहण करने में तत्परता ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि पानी प्राप्ति के एक से अधिक विकल्प होते हुए भी तैयार ढांचे के मूल स्वरूप को निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर बिगाड़ रहे हैं। यह स्थितियां तो तब है जब समाज की समृद्धि के लिए सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उनमे होने वाले अन्यायों को रोकते हुए 'खेत को पानी' देना शासन का है सर्वोपरि धर्म है।

परियोजना का नाम परिवर्तन राम जल सेतु का विरोध तो कोई नहीं करेगा किंतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम में यथार्थ का बोध होता था, वैसी स्थिति नए नाम में नहीं है। धरातल की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कितनी सही है, इसका आकलन पाठकों पर ही छोड़ना अधिक युक्तिसंगत है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत

'शिक्षक की हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है'

- **पूर्वांचल जन चेतना समिति व यूनेस्को ने 74 शिक्षकों का सम्मान किया**

भीलवाड़ा, (निसं)। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्वांचल जन चेतना समिति व जिला यूनेस्को एसोसिएशन तथा मणी एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आजाद नगर स्थित पीएफसी गार्डन में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के 71 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं कवि प्रहलाद पारीक ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) रामेश्वर बाल्दी थे। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली, जिला यूनेस्को एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित अग्रवाल, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन मंजू पोखरना, आजाद शर्मा, जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा, मनी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष विभोर त्रिवेदी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम सयोजक रजनीश वर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के 71 शिक्षक और शिक्षिकाओं को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही हमारे जीवन के सबसे अहम गुरु होते हैं, जो हमें भविष्य में सही रास्ता दिखाने, मार्गदर्शन करने व जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारे लिए किसी भगवान से काम नहीं होते हैं। शिक्षक की हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्वांचल जन चेतना समिति के संस्थापक अध्यक्ष रजनीश वर्मा ने संस्था के बारे में जवाहर फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत किया जा रहे हैं कार्यों के बारे में भी बताया साथ ही कहा कि पूर्वांचल जन चेतना समिति यूनेस्को के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगी। समारोह में मणी एजुकेशन सोसायटी की सचिव अनुराधा झा के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें कई बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर जिला यूनेस्को एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश जैन, सचिव जगदीशचंद्र मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विशाल विजयवर्गीय, संगठन मंत्री कमलेश जादू, मणी एजुकेशन सोसाइटी के ऋषि राज, मीडिया प्रभारी बृजेश शर्मा, वैभव जोशी, पूर्वांचल जन चेतना समिति के सदस्य कामेश्वर झा, आकाश झा, फुल झा, शिल्पी, चिराग टेलर, सहित सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाये व संस्थाओं के सभी पदाधिकारी सदस्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को की प्रवक्ता मधु लोढ़ा ने किया।

अनंत चतुर्दशी पर रणछोड़ मंदिर में अनुष्ठान

डूंगरपुर, (निसं)। अंनत चतुर्दशी के अवसर पर महिलाओं ने घर परिवार के सुख–समृद्धि की कामनाओं के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का दौर दिन भर चला। शनिवार प्रातः से रिमझिम व मूसलाधार बारिश के बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जनजाति क्षेत्र की महिलाएं, बालिकाएं, युवक व पुरूष पूजा सामग्री लेकर फौज का बडला स्थित रणछोड़ मंदिर, सुथारवाडा स्थित विश्वकर्मा मंदिर सहित विभिन्न महादेव मंदिरों में पहुंचकर नारियल वधेरा तथा भगवान से सुख–समृद्धि की कामना की। इस दौरान अनंत चतुर्दशी का रक्षा सूत्र धारण किया। धर्म प्रेमियों ने उपवास भी रखा। प्रातः से ही फोज का बडला स्थित रणछोड़ राय मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी।

राशिफल रविवार 7 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, रविवार, विक्रम संवत 2082, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 9:14 तक, सुकर्मा योग प्रातः 9:22 तक, विष्टि करण प्रातः